mada. No other schemes have been sponsored b y the State Govern ment during the Third Plan period so far.

OFFICERS DEPUTED BY THE C.W.P.C. FOR TRAINING ABROAD

217. S HRI NIRANJAN SINGH: W ill the Ministe r of I RRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) how many o f th e officers who were deputed for train ing abroad in th e year 1962-63 b y the C entral Water and Power Commission have returned to India; and

(b) where were they trained, the .subjects in which they were tr ained an d the p laces where they are employed after their return?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) Sixteen.

(b) A s tatement is attached. [S ee Appendix XLV, Annexure No. 10].

"VISIT OF INDIAN BANANA DELEGATION TO MIDDLE EAST

218. S HRI N. SRI RAMA REDDY: Will the Mi nister of INTERNATIONAL TRADE be pleased to state whether an Indian ban ana del egation recen tly visited sever al countries in the Middle East?

THE MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE (SHRI MANUBHAI SHAH) : Yes, Sir.

DBCISIONS TAKEN AT THE CONFERENCE OF INCOME-TAX COMMISSIONERS

219. S HRI NIRANJAN SINGH: W ill the Minister of F INANCE be pleased to state the decisions taken recently at the conf erence of Commissioners of Income-tax h eld at Delh i regarding realization of arrears of tax es timated at more th an Rs. 175 cro res and th e •evasion of income-tax?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI) : The Conference does not take any decisions. Suggestions were, however, m ade at the Confer ence of Com - missioners of Incom e-tax h eld re cently at Delhi regarding the recovery of arrears of tax and che cking evas ion of inco me-tax. Th ese suggestions will be ex amined b y th e Centr al Board of Revenue and Gover nment in the light of fur ther reports wh ich will be submitted by the Commissioners.

कम्पनियों के आडिट के लिए नियम

२२०. **श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दफ्तरी-शास्त्री समिति की रिपोर्ट के अनुसार कम्पनियों के आडिट के लिये जो नियम बनाने का सुझाव था, उस के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

t [**RULES FOR AUDIT OF COMPANIES**

220. S HRI V. M. CHORDIA: W ill the Minister of F INANCE be pleased to s tate what progress has so far been made in respect of the proposal to frame rules for the audit of companies in accordance wi th the Daf tary-Sastri Committee Report?]

वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) माननीय मंत्री सम्भवत: दफ्तरी-शास्त्री समिति की इस सिफारिश का जिक्र कर रहे हैं कि चार्टर-प्राप्त लेखाकार संस्थान (इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) की परिषद् (कौंसिल) से कहा जाय कि वह उन लोगों के हित की रक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए सरकारी कम्पनियों की लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में एक संहिता (कोड) तैयार करे जिन्हों ने निदेशक-मण्डल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) का विश्वास कर के शेयर खरीदे है । अगर ऐसा है, तो संस्थान की परिषद् को यह बात पहले ही बता दी गयी

†[ ] English translation.

है । परिषद की एक उप-समिति ने संहिता का मसविदा भी तैयार कर लिया है जिस में उन सिद्धान्तों को शामिल किया गया है जिन के अनुसार लेखा परीक्षकों को आम तौर से कम्पनियों के लेखे की जांच करनी चाहिये । यह मसविदा परिषद् के सदस्यों के विचार जानने के लिये उन के पास भेज दिया गया है । उन विचारों के आधार पर संहिता को अन्तिम रूप दिया जायगा और तब उसे परिषद् के कार्य करने वाले सभी सदस्यों के पास उन के मार्गदर्शन के लिए भेज दिया जायगा ।

t[THE MINISTER or FINANCE (SHEI T. T. KRISHNAMACHARI) : The Hon 'ble M ember is presumably referring to the recommendation of the Daftar y-Sastri Com mittee th at th e Council of t he Institute of Chartered Accountants should be called upon to formulate a cod e in regard to the audit of th e accounts of pu blic companies with spec ial reference to safeguarding th e inter ests of members of the public who have put their faith in the bo ard of directors an d contributed to the share capital. If this is so , the Coun cil of the Institute is already seized of the matter. A sub-Co mmittee of the Council has since prepared a dr aft 'code' embodying the principles which should generally be followed by th e auditors in auditing the accoun ts of companies. Th e draft has been circul ated to the members of the Council for comments. In the light of thes e comments, this code will be finalised and issued to all practising members of the Institute for their guidance.]

अफीम की काश्त के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी नियमों में संशोधन

२२१. **श्री विमलकुमार** सरालालजी **चोरड़िया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में अफीम की काश्त के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के क्या प्रयोजन थे ; और

(ख) ये संशोधन किस किस तारीख को किये गये ?

t [**AMENDMENT OF RULES RELATING TO GRANT OF LICENCES FOR POPPY CULTIVATION**

221. S HRI V. M. CHORDIA: W ill the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the purpose for which the rules relating to the grant of licences for popp y cultivation were amended during the last five years; and

(b) the dates on which these amendments were made?]

वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) (क) पोस्त की काश्त के लिए लाइसेंस देने की नीति पर हर साल इसलिए विचार करना पड़ता है कि आवश्यकता के अनुसार खेती के आवश्यक क्षेत्र के लिये लाइसेंस दिये जा सकें । ऐसा करते हुए इस बात का प्रयत्न भी किया जाता है कि नीचे दिये गये उपायों द्वारा उपज के गैर-कानूनी तौर से हटाये जाने के खतरों को कम किया जा सके और औसत उपज में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि की जा सके :—

(१) अकुशल खेतिहरों और अनुत्पादक भूमि को अलग करना ।

(२) काश्त को एक दूसरे से लगे हुए क्षेत्रों तक सीमित रखना ।

(३) कम खर्चीले और ज्यादा अच्छे नियंत्रण के लिए उपयुक्त स्थिति पैदा करना ।

(ख) लाइसेंस जारी करने के सिद्धान्तों की सूचना नशीली वस्तु सम्बन्धी आयुक्त